एम. जैन

आदर्श कुमार गोयल-एसीजे और अजय कुमार मित्तल, न्यायमूर्ति के समक्ष

मैसर्स अमित एंटरप्राइजेज अपने

प्रोपराइटर ज्ञान चंद के माध्यम से, **-अपीलकर्ता**

बनाम

भारत संघ और *अन्य*,-- *प्रतिवादी*

2011 की सिविल रिट याचिका संख्या 6732

9 मई, 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962- धारा 17,18,24,46,110, 111-जब्ती ज्ञापन को रद्द करना और सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा बंद और रुके हुए माल की निकासी की अनुमति - धारा 2(34) ओपन जनरल लाइसेंस स्कीम के तहत दक्षिण अफ्रीका से आयातित भारी पिघलने वाला स्टील स्क्रैप जिस पर कोई सीमा शुल्क संलग्न नहीं है- प्रतिवादी ने इस आधार पर मंजूरी से इनकार कर दिया कि आयातित सामग्री को स्क्रैप नहीं किया गया था लेकिन फिर से रोल करने योग्य मीटर जिसे 5% मूल सीमा शुल्क लगता था- अच्छा बंद हो गया- शारीरिक रूप से जांच की गई - चार्टर्ड इंजीनियरों द्वारा राय - मूल्यांकन राशि का आकलन किया गया और याचिकाकर्ता ने विलंब शुल्क से बचने के लिए माल की अनंतिम रिलीज की मांग की।

विवाद वर्गीकरण और मूल्यांकन के बारे में है और याचिकाकर्ता ने बैंक गुआ रेंट की विभागीय मूल्यांकन

आवश्यकता के अनुसार माल के 25% मूल्य के बराबर मनमाना और ***दुर्भावनापूर्ण*** ई-माल जारी करने का आदेश पारित किया है। केवल तथ्य यह है कि जब्ती की शक्ति का मतलब यह नहीं है कि इस तरह की शक्ति का उपयोग यांत्रिक या मनमाने ढंग से किया जा सकता है, बिना किसी औचित्य के। याचिका की अनुमति दी।

(11, 12, 14 और 15 के लिए)

श्री जेअग्रवाल बंसल, एडवोकेट विद सौरभ कपूर और श्री रीएसहभ कपूर, एडवोकेट, ***याचिकाकर्ता के लिए***

कमल सहगल, अधिवक्ता, ***प्रतिवादियों के लिए।***

आदर्श कुमार गोयल, एसीजे.

(1) यह याचिका जब्ती ज्ञापन को रद्द करने और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ("अधिनियम") के प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त और हिरासत में लिए गए माल की निकासी की अनुमति देने की मांग करती है।

(2) याचिका में निर्धारित मामला यह है कि याचिकाकर्ता ने शून्य मूल सीमा शुल्क के अधीन ओपन जनरल लाइसेंस योजना के तहत दक्षिण अफ्रीका से 'हैवी मेल्टिंग स्टील स्क्रैप' (एचएमएसएस) का आयात किया। याचिकाकर्ता ने जनवरी, 2011 में अलग-अलग तारीखों पर 31 कंटेनरों में उक्त माल को मंजूरी देने के लिए सात बिल ऑफ एंट्री दायर किए लेकिन सीमा शुल्क अधिकारियों ने इस आधार पर मंजूरी की अनुमति नहीं दी कि आयातित सामग्री स्क्रैप नहीं थी बल्कि 5% मूल सीमा शुल्क पर फिर से रोल करने योग्य धातु थी। अधिनियम की धारा 110 के तहत माल जब्त किया गया था। माल की भौतिक जांच की गई और चार्टर्ड इंजीनियरों की राय ली गई कि खेप के एक हिस्से में चंद्रमा के टुकड़े थे जबकि शेष पुराने जंग लगे थे लेकिन इस्तेमाल किए गए पाइप नहीं थे। याचिकाकर्ता ने उक्त चार्टर्ड इंजीनियरों द्वारा मूल्यांकन किए गए मूल्यांकन के अनुसार शुल्क की राशि जमा की और विलंब शुल्क से बचने के लिए माल की अनंतिम रिहाई की मांग की। याचिकाकर्ता ने खेप के उत्परिवर्तन के लिए भी अनुरोध किया। माल जारी नहीं किया गया है; यह याचिका दायर की गई है।

(3) याचिका में उठाया गया मुख्य विवाद यह है कि जब माल की निकासी के लिए अधिनियम की धारा 46 के तहत प्रविष्टि का बिल दायर किया जाता है, तो सक्षम अधिकारी को धारा 17 के तहत शुल्क का आकलन करने की आवश्यकता होती है और उक्त शुल्क के भुगतान पर, माल को मंजूरी देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

धारा 24 में आयातक के अनुरोध पर माल के उत्परिवर्तन का प्रावधान है ताकि माल को किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त बनाया जा सके और यह दावा किया जा सके कि शुल्क की कम दर देय थी। धारा 18 मेंशुल्क के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान है जहां मूल्यांकन के बारे में अंतिम दृष्टिकोण बनाने के लिए किसी और जांच की आवश्यकता है। धारा 110 माल की जब्ती का प्रावधान करती है यदि यह मानने के कारण हैं कि माल जब्त करने के लिए उत्तरदायी है। धारा 111 में उन वस्तुओं का प्रावधान है जिन पर माल जब्त किया जा सकता है। जब्ती के आधारों में सीमाशुल्क पत्तन के अलावा किसी अन्य स्थान पर लदान/उतराई, विनिदष्ट मार्ग से भिन्न मार्ग अपनाना, निषिद्ध वस्तुओं का आयात, वस्तुओं के वर्गीकरण और उनके मूल्य के बारे में सूचना पत्र में गलत घोषणा करना शामिल है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है जो उक्त बोर्ड द्वारा जारी अनुपूरक नियमावली अध्याय 16 में निहित है जिसमें माल की निरंतर रोक के कारण आयातक को होने वाली कठिनाई से बचने के लिए शीघ्र मूल्यांकन/जांच का प्रावधान है। उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि आयातित माल को तब तक रोक कर नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि साधारण मूल्य/वर्गीकरण विवादों पर प्रतिबंध न हो । जब्ती की शक्ति का प्रयोग अधिनियम की धारा 2 (34) के तहत परिभाषित एक सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना है, अर्थात, वह अधिकारी जिसे स्पष्ट रूप से उन कार्यों को सौंपा गया है। **सीमा शुल्क आयुक्त *बनाम* सैयद अली में,**[1] माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 2 (34) के तहत सक्षम अधिकारी को विशेष रूप से इस तरह कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि माल को हिरासत में लेने और उसे हिरासत में रखने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र और मनमानी के बिना

[1] 2011 (265) ईएलटी 17 (एस.सी.) = 2009 (234) ईसीआर 203 (6)

थी।

(4) अपने जवाब में प्रतिवादियों का रुख यह है कि वर्गीकरण और मूल्यांकन के विवाद के कारण माल को रोक लिया गया था। माल को शुल्क के भुगतान से बचने के लिए गलत तरीके से एचएमएसएस के रूप में वर्णित किया गया था और एक बार गलत घोषणा होने पर, माल अधिनियम की धारा 111 के तहत जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है। चार्टर्ड इंजीनियर्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि अंडरवैल्यूएशन है। राजस्व आसूचना निदेशालय के सभी अधिकारी सीमा शुल्क के अधिकारी थे और उन्हें माल जब्त करने के लिए उचित अधिकारियों के रूप में माना जा सकता था। निम्नलिखित शर्तों के अधीन माल को रिलीज करने के लिए 3 मई, 2011 को अनंतिम रिलीज का आदेश पारित किया गया था -

(1) विभेदक शुल्क के भुगतान पर।

(11) जब्त माल के पूरे मूल्य के लिए एक बांड प्रस्तुत करने पर, अर्थात 1,24,85,736 रुपये।

(111) जब्त माल के पूर्ण बाजार मूल्य के 25% के बराबर B/G प्रस्तुत करने पर।

(112) एक शपथ पत्र के रूप में एक घोषणा प्रस्तुत करने पर कि पार्टी अधिनिर्णय या अभियोजन कार्यवाही के दौरान जब्त माल के मूल्य और पहचान को चुनौती नहीं देगी, यदि कोई हो।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है।

(6) विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या माल की निरंतर हिरासत को उचित ठहराया जा सकता है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब्ती करने वाला

(6) - 2009 (234) ईडीएफ 203

अधिकारी अधिकृत नहीं था और वर्गीकरण और मूल्यांकन के विवाद ने माल को जब्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया था कि माल के पूर्ण बाजार मूल्य के 25% के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त और याचिकाकर्ता पर आगे की शर्त को लागू करना घोषणा या अभियोजन के दौरान माल के मूल्य को चुनौती नहीं देगा, मनमानी शर्तें थीं। उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में, निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया है: -

(i) **सेंचुरी मेटल रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड *बनाम* यूनियन ऑफ इंडिया**[2] **।**

(ii) **मैसर्स बजरंगबली ट्रेडिंग कंपनी *बनाम* भारत संघ और अन्य,** 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या/3786 का निर्णय 17 मार्च, 2011 को लिया गया (पी एंड एच);

(iii) **भूमि सुधार केमिकल इंडस्ट्रीज** बनाम **संयुक्त निदेशक, डीआरआई, लुधियाना** [3]

(iv) **सोनिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड *बनाम* उप निदेशक निदेशालय**[4]**।**

(v) **मैपसा टेप्स प्राइवेट लिमिटेड *बनाम* भारत संघ**[5]**, (5).**

(8) दूसरी ओर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक

[2] 2009 (234) ईएलटी (पी एंड एच)

[3] 2007 (213) ईएलटी 494 (पी एंड एच)

[4] 2007 (216) ईएलटी 687 (पी एंड एच)

[5] 2006 (201) ईएलटी 7 (पी एंड एच एचसी)

(6) - 2009 (234) ईडीएफ 203

बार जब माल जब्त करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो राजस्व जब्त होने पर माल जारी नहीं कर सकता है, माल राज्य में निहित होगा और राजस्व के हितों की रक्षा के लिए कम से कम 25% बैंक गारंटी की आवश्यकता आवश्यक थी। **टी. एल. वर्मा एंड कंपनी प्राइवेट** लिमिटेड बनाम भारत संघ[6], **और मैसर्स कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड** *बनाम* **भारत संघ और अन्य,** 2008 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1391 4 में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिसका निर्णय 5 दिसंबर को किया गया था। (ख) भारत सरकार ने 2008 में 2008 के मामले में एक निर्णय लिया था जिसमें जब्त माल के मूल्य के 10% के संबंध में बैंक गारंटी की शर्त को इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि यह सुविधा धारा 10 की धारा अधिनियम की धारा 110

(9) अब हम इसमें शामिल मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

(10) हालांकि, प्रथम *दृष्टया, जब्ती* को प्रभावित करने वाले अधिकारी को ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी नहीं दिखाया गया है और न ही वर्गीकरण और मूल्यांकन के एक साधारण विवाद पर जब्ती के लिए औचित्य दिखाया गया है, हम इन प्रश्नों को अंतिम रूप से उचित कार्यवाही में निर्णय लेने के लिए छोड़ देते हैं वें ई के वें ई स्टैंड को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि इस स्तर पर, जिस राहत को दबाया जाना आवश्यक है, वह उचित शर्तों पर माल को तत्काल जारी करने का था।

(11) हमें इस तर्क में दम लगता है कि यह घोषणा देने की आवश्यकता कि याचिकाकर्ता माल के मूल्य को चुनौती नहीं देगा , अनुचित और मनमाना है।

---

[6] 2009 (234) ईएलटी 203
(6) - 2009 (234) ईडीएफ 203

याचिकाकर्ता को माल के मूल्य और वर्गीकरण के रूप में अपने संस्करण पर जोर देने से वंचित नहीं किया जा सकताहै। यदि ऐसी शर्त लगाने की अनुमति दी जाती है, तो विभाग एकतरफा रूप से किसी भी मूल्यांकन का आरोप लगा सकता है और माल को तब तक हिरासत में रखना जारी रख सकता है जब तक कि प्रभावित पक्ष मूल्यांकन को चुनौती वापस लेने के लिए सहमत न हो। यह न्याय से वंचित करने के समान होगा। इसी प्रकार, जब्त किए गए माल के पूर्ण बाजार मूल्य के 25% के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार मनमानी है। केवल तथ्य यह है कि टी. **एल. वर्मा** और **मैसर्स कुंदन राइस मिल्स** मामले में इस न्यायालय द्वारा बैंक गारंटी के 10% की शर्त को बरकरार रखा गया था, प्रत्येक सुविधा में ऐसी शर्तें लगाने का औचित्य नहीं हो सकता। उन आसान मामलों में, यह न्यायालय संतुष्ट था कि आयातकों ने धोखाधड़ी की रणनीति अपनाई थी, जो *प्रथम दृष्टया,* राय या जब्ती को उचित ठहराती थी

---

(6) - 2009 (234) ईडीएफ 203

माल की। उक्त निर्णय नजरबंदी में हर आसानी पर लागू नहीं हो सकते। जब्ती के दायित्व का मर्क आरोप पर्याप्त नहीं है। जब्ती के दायित्व के बारे में परिस्थितियों और आधारों की राय न्यायिक जांच के लिए खुली है।

(12) माल को निरोध करने की शक्ति एक कठोर शक्ति है और इस तरह की शक्ति के प्रयोग को इसके दुरुपयोग की जांच करने के लिए सुरक्षा उपायों द्वारा बचाव किया जाना चाहिए और इसके प्रयोग को केवल उस स्थिति तक सीमित करना होगा जहां कानून द्वारा इसका प्रयोग करने का इरादा है। शक्ति का अस्तित्व और पीओवर आर्क का प्रयोग स्वतंत्र। केवल तथ्य यह है कि डॉक्स को जब्त करने की शक्ति है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग यांत्रिक या मनमाने ढंग से किया जा सकता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी को सख्ती से इसका औचित्य साबित करना चाहिए। जिसउद्देश्य के लिए यह शक्ति प्रदान की गई है, उसके प्रयोग के लिए शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना होगा और नागरिक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(13) जैसा कि आयोजित **मैप्सा टेप्स प्राइवेट लिमिटेड** में किया गया है, कर की चोरी को रोकने के लिए तलाशी और जब्ती की शक्ति को एक नागरिक के अधिकार के साथ अस्थायी हस्तक्षेप के रूप में बरकरार रखा गया है। साथ ही, जब्ती न केवल संपत्ति के अधिकार का अतिक्रमण है बल्कि निजता का अधिकार भी है। इस तरह के अधिकार केवल निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया से प्रभावित हो सकते हैं जैसा कि **मेनका गांधी** *बनाम* **भारत संघ**[7] में आयोजित किया गया है। इस पहलू का उल्लेख करते हुए, **जिला रजिस्ट्रार और कलेक्टर, हैदराबाद और**

[7] एआईआर 1978 एससी 597

अन्य बनाम केनरा बैंक आदि [8] के मामले में हाल ही में दिए गए निर्णय में यह देखा गया था कि

"33. गोपनीयता में घुसपैठ द्वारा हो सकता है- (1) विधायी प्रावधान। (2) प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश, और (3) न्यायिक आदेश, विधायी घुसपैठ को संविधान द्वारा गारंटीकृत तर्कसंगतता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए न्यायालय प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की तुलना में घुसपैठ की आनुपातिकता पर जा सकता है। (2) जहांतक प्रशासनिक या कार्यकारी कार्रवाई का संबंध है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका उचित होना उचित है (3) न्यायिक वारंट के रूप में, अदालत के पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए कि तलाशी या जब्ती की आवश्यकता है और इसे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि खोज या जब्ती विशेष राज्य हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक है ।इसके अलावा, जैसा कि पहले कहा गया है, आम कानून ने दुर्लभ अपवादों को मान्यता दी है जैसे कि वारंट रहित खोज की जा सकती है, लेकिन ये अच्छे विश्वास में होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सबूतों को संरक्षित करना है या व्यक्ति या संपत्ति को अचानक खतरे को रोकने का इरादा है। (आपूर्ति की गई रेखांकित)।

XX XX XX XX XX

55. **श्रीमती मनए** का **गांधी** *बनाम* **भारत संघ और अन्य**(1978)

[8] एआईआर 2005, एससी 186

1एससीसी 248 - 7-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, पी.एन. .1 (जैसा कि उनके लॉर्ड शिप तब था) ने माना कि अनुच्छेद 21 में अभिव्यक्ति 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' व्यापक आयाम की है और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं (महत्त्व सन्निविष्ट) के अंतर्गत अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हुए उनमें से कुछ को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रतिष्ठित करने का दर्जा दिया गया है और अनुच्छेद 19 (महत्त्व सन्निविष्ट) के अंतर्गत अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी कानून को ट्रिपल परीक्षण को पूरा करना चाहिए; (i) इसे एक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए: (ii) प्रक्रिया को अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त एक या अधिक मौलिक अधिकारों के परीक्षण का सामना करना चाहिए, जो किसी दी गई स्थिति में लागू हो सकते हैं; और (iii) यह अनुच्छेद 14 के संदर्भ में परीक्षण के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। जैसा कि अनुच्छेद 14 द्वारा प्रतिपादित परीक्षण अनुच्छेद 21 में भी व्याप्त है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के साथ हस्तक्षेप को अधिकृत करने वाला कानून और प्रक्रिया भी सही और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं होना चाहिए। यदि निर्धारित प्रक्रिया अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, तो यह अनुच्छेद 21'* के अर्थ के भीतर कोई प्रक्रिया नहीं होगी।

(14) तर्कसंगतता अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा होने के नाते, आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है ताकि असमान को समान नहीं माना जा सके। 'विवेक का प्रयोग उस गलत के अनुपात में होना

चाहिए जिसके कारण कार्रवाई हुई है। ओम **कुमार** *बनाम* **भारत संघ (9)** में आनुपातिकता के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, जिसमें यह देखा गया था।

"28. "आनुपातिकता" से, हमारामतलब इस सवाल से है कि क्या मौलिक अधिकारों के प्रयोग को विनियमित करते समय, उचित या (9) एआईआर 2000 एससी 3689

> विधानमंडल या प्रशासक द्वारा उपायों का सबसे कम प्रतिबंधात्मक विकल्प बनाया गया है ताकि कानून के उद्देश्य या प्रशासक आदेश के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, जैसा भी मामला हो। सिद्धांत के तहत, अदालत यह देखेगी कि *विधायिका और* प्रशासनिक *प्राधिकरण* "उन प्रतिकूल प्रभावों के बीच *एक उचित संतुलन* बनाए रखें जो कानून या *प्रशासनिक* आदेश का व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रता या हितों पर उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हो सकता है जिसे वे सेवा करने का इरादा रखते थे"। विधायिका और प्रशासनिक प्राधिकरण चाप। हालांकि, विवेक या विकल्पों की एक श्रृंखला का एक क्षेत्र दिया गया है, लेकिन क्याकिया गया विकल्प अधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन करता है या नहीं, यह अदालत के लिए है। थाटी वह है जो आनुपातिकता से अभिप्राय है।

(15) वर्तमान आसानी में, विवाद वर्गीकरण और मूल्यांकन के बारे में है। याचिकाकर्ता ने पहले ही विभाग के मूल्यांकन के अनुसार शुल्क का भुगतान कर दिया था। विभाग ने त्वरित जांच के दिशानिर्देशों को ध्यान में नहीं रखा है और मूल्यांकन/वर्गीकरण के साधारण विवाद पर माल को हिरासत में नहीं लिया है। विभाग ने जब्ती की शक्ति के प्रयोग के लिए *प्रथम दृष्टया* आसानी नहीं दिखाई है और शक्ति के अस्तित्व पर भरोसा किया है। इन परिस्थितियों में, माल के मूल्य के

25% के बराबर बैंक गारंटी की आवश्यकता स्पष्ट रूप से मनमानी और *दुर्भावनापूर्ण है* और उक्त शर्त को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(16) तदनुसार, इस याचिका को अनुमति दी जाती है औरअनंतिम रिलीज के आदेश में निहित शर्तों के अधीन जारी करने के लिए निर्देशित किया जाता है, सिवाय याचिकाकर्ता द्वारा घोषणा की आवश्यकता के कि यह बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के मूल्य और आवश्यकता पर विवाद नहीं करेगा। हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह आदेश विवाद के गुणों को प्रभावित नहीं करेगा, जिसे स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार अंतिम रूप से स्थगित किया जाएगा।

एम. जैन

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा